पीट्सबर्ग में G-20 की बैठक में प्रधानमंत्री का भाषण- plenary सत्र

25 सितम्बर 2009

राष्ट्रपति महोदय,

सबसे पहले, इस सम्मेलन के शानदार प्रबंधन और आपकी गर्मजोशी भरी मेहमान -नवाजी के लिए आपका धन्यवाद।

हमने विश्व अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उसके सामने आ रही जटिल चुनौतियों के बारे में चर्चा की। मैं इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूँगा कि विकासशील देशों के लिए इसके क्या मायने हैं।

हम सभी जानते हैं कि ये देश किसी भी प्रकार से इस संकट के लिए जिम्मेदार नहीं थे परंतु, कई मायनों में उन पर इस मंदी का काफी असर हुआ। इस संकट के सामने आने के सात साल पूर्व विकासशील देशों का सकल घरेलू उत्पाद 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2009 में इसका विकास केवल 1.5 प्रतिशत की दर से होगा जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में गिरावट दर्शाएगा।

यह सच है कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह के अनुभव होते हैं। एशिया के देशों की स्थिति सामान्यतः अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी रही। उप-सहारा अफ्रीकी देशों और कई अन्य क्षेत्रों के देशों पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा।

भारत पर भी इसका असर पड़ा परंतु, अन्य एशियाई देशों के समान, हमने परिस्थिति के अनुसार इस संकट को झेल लिया। चार वर्ष तक 9 प्रतिशत की बढ़त के साथ हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2008-09 में 6.7 प्रतिशत की धीमी रफ्तार पर रही। वर्ष 2009 में सूखे के बावजूद, जो कृषि उपज पर प्रभाव डालेगा, हम वर्ष 2009-10 के दौरान 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा करते हैं और फिर अगले वर्ष 7 से 7.5 प्रतिशत की वार्षिक बढ़त दर से उबरने की आशा रखते हैं। यह मजबूत विकास की दर वर्ष 2008-09 की दूसरी छःमाही में शुरू किए गए मजबूत प्रोत्साहक उपायों के चलते भी रही जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी जारी हैं।

तथापि हममें से कुछ देशों के तुलनात्मक तरीके से अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इस संकट ने विकासशील दुनिया पर प्रभावी असर

नहीं डाला है। यह तथ्य, कि विकासशील देशों के एक गुट के रूप में 1.5 प्रतिशत विकास दर में गिरावट आएगी, इसके असर को दर्शाता है।

विकासशील दुनिया के करीबन 9 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से नीचे आ जाने की संभावना है। कम राजस्व के कारण ग्रामीण आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम खर्च होगा इससे न केवल भविष्य के विकास पर असर पड़ेगा बल्कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देरी होगी। सामाजिक और राजनैतिक तनाव बढ़ सकते हैं जिससे काफी जरूरी ढांचागत सुधार और तालमेल के पक्ष में एक राष्ट्रीय आम सहमति पर असर पड़ेगा।

संकट से पहले बेहतर प्रतीत होने वाली केन्द्राभिमुख होने की संभावनाएं कम हुई हैं। हमें इन घटनाओं से निपटने और विकासशील दुनिया की विकास की गति को पुनः स्थापित करने के लिए कदम उठाने होंगे।

सर्वप्रथम इस समस्या के संपूर्ण निराकरण के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द अपनी सामान्य स्थिति पर लाने के उपाय सुनिश्चित करने होंगे। इसके लिए एक ऐसी प्रतिबद्धता, कि प्रोत्साहक उपायों को समय से पूर्व वापिस नहीं लिया जाएगा, की जरूरत है। हमें एक व्यवस्थित तरीके से इस संकट से सही समय पर बाहर निकलने की योजना बनानी होगी परंतु वह समय अभी नहीं आया है। विश्व अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आ सकती है परंतु 2010 के अंत तक इसके 3 प्रतिशत विकास दर तक पहुंचने की संभावना नहीं है।

विश्व अर्थव्यवस्था की दुविधापूर्ण स्थिति से विकासशील देशों के लिए निर्यात मांग में काफी नुकसान होता है। वर्ष 2009 में गैर तेल उत्पादक देशों के निर्यात में, पिछले वर्ष के मुकाबले करीबन 900 बिलियन डालर की कमी आने का अंदाजा है। वे इससे पूर्व कई वर्षों तक किए गए पूर्वानुमानों से भी काफी निचले स्तर पर रहेंगे। इससे विकासशील देशों में उत्पादन, आय और रोजगार में कमी आएगी।

जी-20 द्वारा अनुदान बढ़ाने के लिए किए गए उपायों से मदद मिलेगी और वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का नमूना है। तथापि, हस्तांतरित किए जाने वाले इन अनुदानों से विकासशील देशों को अपनी मंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों का केवल भुगतान करने में सहायता मिलेगी। वे उनके निर्यातों में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकेंगे।

विकासशील देशों में विकास की गति को पुनः पटरी पर लाने के लिए हमें घरेलू आवश्यकताओं के अन्य पहलुओं का विस्तार कर निर्यात नुकसान की भरपाई करनी होगी। सबसे सही विकल्प निवेश बढ़ाना है। विकासशील देशों में एक ऐसा क्षेत्र जहां अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है वह है आधारभूत संरचना जिसमें ऊर्जा, परिवहन और लोक सेवाओं के लिए अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। इन निवेशों को आवश्यकताओं से पहले किया जा सकता है और इसलिए ये प्रति चक्रणीय गतिविधि का आदर्श रूप हैं।

विश्व बैंक और अन्य क्षेत्रीय विकास बैंक ऐसे निवेश को वित्तपोषित कर एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें उभरते बाजार वाले देशों को अपनी आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण सहायता की राशि बढ़ानी होगी। ऐसे देश सामान्य समय के दौरान पूंजी बाजार पर आधारित होते हैं परंतु इन्हें मध्य दौर में जब तक कि पूंजी बाजार उबर नहीं पाता, तब तक सहायता की जरूरत होगी। गरीब, कम आय वाले देशों की पूंजी बाजार तक बहुत कम पहुंच थी। उनके लिए अधिक समयावधि के लिए उचित शर्तों पर वित्त उपलब्ध कराना होगा।

खोई हुई निर्यात मांग का स्थान लेने के लिए विकासशील देशों में निवेश बढ़ाने की मांग के लिए एक रणनीति बनाने से न केवल विकासशील देशों को अपने विकास में मदद मिलेगी बल्कि इससे विश्व व्यवस्था को व्यापक रूप से पटरी पर लाने में योगदान मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि निवेश में निर्यात पहलू के मुकाबले आयात पहलू काफी अधिक है। जिसका यह अर्थ है कि प्रारंभिक मांग में बढ़त का काफी हिस्सा विश्व अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।

विश्व बैंक ने यह घोषणा की है कि अगले तीन वर्षों तक आईबीआरडी द्वारा दिए जाने वाले ऋण में 100 बिलियन डालर तक की बढ़ोत्तरी की जाएगी। यह प्रशंसनीय है। तथापि, अगर आईबीआरडी के पूंजी आधार में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती तो उन्हें तीन वर्ष की अवधि के अंत में दिए जाने वाले ऋण में कमी लाते हुए संकटपूर्व स्तर से भी अधिक कमी करनी होगी। यह वास्तव में स्वीकार्य नहीं है।

इसलिए आईबीआरडी की पूंजी को दोगुना करना होगा। इसी तरह अन्य प्रादेशिक विकास बैंकों के लिए पूंजी की आवश्यकता है।

मैं मानता हूं कि *रीकैपीटलाइजेशन* के लिए अतिरिक्त लोक संसाधन के लिए प्रतिबद्धता में हिचकिचाहट हो सकती है। तथापि, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन संस्थानों के लिए जो आवश्यकताएं हैं वे औद्योगिक देशों में निजी वित्तीय व्यवस्था को स्थिर करने के लिए भारी मात्रा में दिए जाने वाले आम जनता के पैसे के मुकाबले काफी कम हैं। विकासशील देशों के लिए कुछ अतिरिक्त कोशिश करना गलत नहीं होगा ताकि वे उस संकट के बाद के असर से उबर सकें जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं थे।

अंततः राष्ट्रपति जी मैं व्यापार पर कुछ कहना चाहूंगा। निर्यात बाजारों में आई गिरावट से यह जरूरी हो जाता है कि विकासशील देशों द्वारा बाजार में प्रवेश संरक्षणवादिता द्वारा बाधित न किया जाए। मैं मानता हूं कि जब विकास की गति धीमी होती है और बेरोजगारी ज्यादा होती है, तब संरक्षणवादी दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। यह इस गुट की सामूहिक राजनैतिक अगुवाई की परीक्षा होगी कि क्या हम इन दबावों को हमारे देशों में रोक सकते हैं। मैं यह बात नोट करके खुश हूं कि दिल्ली मिनिस्टीरियल दोहा राउंड वार्ता के लिए गति वापिस लाने में सफल हुई है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यह ऐसा क्षेत्र हैं जहां औद्योगिक देश एक सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी अगुवाई दे सकते हैं।

हमने वित्त पर काफी कुछ किया है और जो कुछ बचा है उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हमें व्यापार स्तर पर मुश्किल पहलुओं से निपटना होगा जो अब मध्यावधि के लिए अधिक जरूरी हैं।

***